बाह्य सहायता से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की अद्यतन स्थितियॉ निम्नलिखित हैंः–

(1) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित **आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना** का वित्त पोषण जापान बैंक फार इन्टरनेशनल (जायका) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना मई, 2008 से संचालित है तथा जुलाई, 2018 में समाप्त होगी। परियोजना की कुल लागत रू0 2887.92 करोड़ है।

यमुना जल की निम्न गुणता के दृष्टिगत इसके शोधन हेतु उच्च तकनीक आधारित सिकन्दरा स्थित जलशोधन संयत्र–II की क्षमतावर्द्धन हेतु 144 एम0एल0डी0 एक अतिरिक्त संयत्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह संयत्र जुलाई, 2014 से क्रियाशील है तथा इससे नगर के लगभग आधे भाग में पेयजल आपूर्ति की जाती है। संयंत्र में प्रयुक्त तकनीक इजराइल/आस्ट्रेलिया से प्राप्त की गई है। योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में अपर गंगा कैनाल पर स्थित पालड़ा फॉल से 130 कि0मी0 लम्बाई में पाइप लाइन बिछाकर आगरा एवं मथुरा नगर को क्रमशः 350 एम0एल0डी0 एवं 25 एम0एल0डी0 गंगाजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है। 130 कि0मी0 के सापेक्ष 121.67 कि0मी0 भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा शेष 8.58 कि0मी0 लम्बाई के लिए प्रयास जारी है। पाइप लाइन बिछाने हेतु 121.67 कि0मी0 के सापेक्ष 100.45 कि0मी0 लम्बाई में पाइप लाइन बिछाने का कर्य पूर्ण हो चुका है।

यमुना नदी पर कैलाश मन्दिर सिकन्दरा, आगरा के समीप सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कन्ड्यूट पाइप एवं फीडर मेन्स के कार्य के अन्तर्गत 2100 मिमी0 व्यास की 98 किमी0 लम्बी Twin Pipe (कुल 194 किमी0) 2800 मिमी0 व्यास की 33 किमी0 लम्बी पाइप लाइन एवं फीडर मेन कार्य के अन्तर्गत 1600 मिमी0 व्यास की 20 किमी0 तथा 800 मिमी0 व्यास की 12 किमी0 लाईन के कार्य कराए जा रहे हैं। सैटलिंग टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं अवशेष कार्यों को कण्डयूट लेइंग के प्रस्तावित कार्यो में समाहित कर लिया गया है। नौलक्खा एवं शाहगंज जोनल पपिंग स्टेशन प्रांगण में भूमिगत जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जीवनी मण्डी एवं सिकन्दरा स्थित 225 एवं 144 एम0एल0डी0 क्षमता के जल शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के कार्यों पर प्रारम्भ से माह अगस्त, 2017 तक रू0 1853.57 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। रू0 1566.71 करोड़ की प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के सापेक्ष रू0 1554.11 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

(2) वन विभाग के अन्तर्गत संचालित की जा रही ''**उ0प्र0 सहभागी वन प्रबन्धन परियोजना**'' जापान बैंक फार इन्टरनेशल कारपोरेशन (जायका) द्वारा वित्त पोषित तथा मार्च, 2008 से संचालित होकर दिसम्बर, 2017 में समाप्त होगी। परियोजना की लागत रू0 575.20 करोड़ है। अवनत वनों का सहभागी पुनर्वास व प्रबन्धन तथा स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि परियोजना के लक्ष्य है।

परियोजना के अन्तर्गत पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, इलाहाबाद, बलरामपुर, झांसी एवं चित्रकूट सम्मिलित किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में बाल वन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चों में वनों एवं वन जीवों के प्रति सशक्त व प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण, मैपिंग, गाइड लाइन मैनुअल तथा हैण्डबुक का कार्य (800 एवं 13) पूर्ण हो चुका है। पी0एम0यू0/डी0एम0यू0/एफ0एम0यू0 का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। सामुदायिक संगठन एवं माइक्रोप्लानिंग तथा एवं लाइवलीहुड का विकास के अन्तर्गत एन0जी0ओ0 का चयन किया जा चुका है। वृक्षारोपण, नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ईको विकास समितियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वेबसाइट विकास का कार्य पूर्ण एवं अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है। बेसलाइन सर्वे तााि परामर्श दात्री सेवाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

परियोजना के कार्यों पर माह अगस्त, 2017 तक रू0 486.12 करोड व्यय किया गया है। प्रतिपूर्ति योग्य अंश 440.78 करोड़ के साप़ेक्ष रू0 428.82 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

(3) परती भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वर्ष 2009 से संचालित ''**उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–तृतीय**'' दिसम्बर, 2017 में समाप्त होगी। परियोजना की कुल लागत रू0 1332.81 करोड़ है। परियोजना सन्त रविदास नगर, जौनपुर,

गाजीपुर, आज़मगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरेया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, बुलन्दशहर, कांशीराम नगर, अम्बेडकर नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर एवं फिरोजाबाद (29 जनपद) में संचालित की जा रही है। परियोजना के कृषक (अनुमानित)–2.40 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति–33 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग–47 प्रतिशत तथा लघु एवं सीमान्त–93 प्रतिशत लाभान्वित होगें।

परियोजना के अन्तर्गत पी0वाई0–6 के अन्तर्गत सोडिक 25000 हेक्टेयर भूमि रिक्लेमेशन के सापेक्ष 17046.98 हेक्टेक्यर लक्ष्य तथा पी0वाई0–7 के अन्तर्गत सोडिक 15000 हेक्टेयर भूमि रिक्लेमेशन के सापेक्ष 22021.68 हेक्टेक्यर लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

इस परियोजना के प्रारम्भ से माह अगस्त, 2017 तक रू0 1099.42 करोड़ व्यय कर लिए गए हैं। रू0 879.54 करोड़ की प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के सापेक्ष रू0 854.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित **''उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना''** के अन्तर्गत परियोजना दिनांक 25.06.2012 से प्रारम्भ हो चुकी है तथा परियोजना 31 मार्च, 2017 में समाप्त होगी। परियोजना के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन एवं जवाबदेही व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा इकाइयों में गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से अभिनव कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित जिला चिकित्सालयों में प्रबन्धकीय एवं प्रणाली क्षमता सुदृढ़ीकरण, जनसामान्य को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराया जाना, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण, स्ट्रेटजिक प्लानिंग सेल, उच्च स्तरीय पैथालाजी जॉच तथा अस्पतालों में मशीनीकृत सफाई एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है। वर्ष 2017–2018 की कार्य योजना के अन्तर्गत पर्यावरण प्रबन्धन, डेटा रिसोर्स सेन्टर, गुणवत्ता आश्वासन, पब्लिक प्राईवेट पाटर्नरशिप, सोशल एकाउंटिबिलिटी, मानव संसाधन, नियोजन एवं बजट स्ट्रेटजिक प्लानिंग एवं उपार्जन वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य लच्छित किया गया है।

परियोजना की कुल लागत रू0 538.55 करोड़ है। परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस परियोजना में माह अगस्त, 2017 तक रू0 202.96 करोड़ व्यय कर लिए गए हैं तथा प्रतिपूर्ति योग्य अंश रू 172.52 करोड़ के सापेक्ष रू0 148.46 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

(5) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत संचालित की जा रही विश्व बैंक से वित्त–पोषित **यू0पी0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना–।। (पैक्ट)–** परियोजना प्रदेश के कुल 16 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यो हेतु रू0 2835.00 करोड के सापेक्ष 70 प्रतिशत (1984.00 करोड़) का IDA ऋण विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत (851.00 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के द्वितीय चरण की प्रस्तावित कार्यावधि 07 वर्ष है। परियोजना दिनांक 24.10.2013 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.10.2020 में समाप्त होगी।

परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में जल संसाधनों की एकीकृत प्रबन्धन व्यवस्था लागू करने हेतु संस्थागत व नीतिगत ढॉचे का सुदृढ़ीकरण किया जाना तथा सिंचाई व जल निकास क्षेत्र का पुनरोद्धार करना एवं कृषकों को सहयोग देकर जल व कृषि की उत्पादकता को इष्ठतम स्तर तक बढ़ाए जाने का है। शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत हैदरगढ़ शाखा प्रणाली के पुर्नस्थापना कार्यों, बेतवा संगठन के अन्तर्गत ललितपुर जनपद में रोहिणी, जामनी, सजनम बांध नहर प्रणालियों के पुर्नस्थापना कार्य, समानान्तर निचली गंगा नहर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार के अन्तर्गत मिट्टी के कार्य, सूचना प्रणाली संगठन हेतु डेस्कटाप, लैपटाप क्रय, स्वारा संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 08 मुख्य बेसिन में रिवर बेसिन अस्सेमेन्ट एण्ड प्लानिंग सिस्टम को विकसित किया जाना आदि कार्य सम्मिलित है।

परियोजना में माह अगस्त, 2017 तक रू0 1163.96 करोड़ व्यय कर लिए गए है तथा रू0 807.72 करोड़ प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के सापेक्ष रू0 770.05 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।

(6) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक से वित्त–पोषित **उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना** लागत रू0 2782.00 करोड़ लागत के ऋण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना का 70 प्रतिशत अंश

अर्थात् रू0 1950.00 करोड़ बाह्य ऋण के रूप में ए0डी0बी0 से प्राप्त होगा तथा 30 प्रतिशत अंश अर्थात् 832.00 करोड़ राज्यांश होगा।

परियोजना वर्ष 2017 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2022 में समाप्त होगी, जिसमें 12 जनपद 12 जनपद (फतेहपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत, सुलतानपुर, देवरिया, कुशीनगर, बुलन्दशहर, लखनऊ, उन्नाव, एटा, कासगंज), 08 मार्ग 431 किमी0 सम्मिलित होंगे तथा 08 प्रमुख जिला मार्गो का 431 किमी0 इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा।